(c) Not applicable.

(d) The achievements during the 7th Plan period (upto 30th Sept., 87) have been above the targets fixed in respect of the number of beneficiaries.

Flood situation in West Bengal

698. SHRI MOSTAFA BIN QUASEM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of severe flood situation in West Bengal;

(b) if so, the total loss suffered by the State;

(c) whether a Central team had visited the affected parts to assess the extent of loss caused;

(d) if so, the details and financial assistance sanctioned by the Union Government for relief measures;

(e) whether floods are a permanent feature in the State; and

(f) if so, the permanent measures taken in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Yes, Sir.

(b) The value of damages to public and private property reported by the state government is Rs. 439 93 crores, besides the loss of 156 human lives and 1391 heads of cattle.

(c) and (d) A Central team visited the State from 5th to 7th September, 1987 to make an on the spot assessment of the situation. On the basis of the report of the Central Team and recommendations of the High Level Committee on Relief, a ceiling of expenditure of Rs. 67.72 crores has been approved to the State Government. In addition Rs. 0 06 crores for increasing vegetable production has also been approved to the State Government.

(e) Flood conditions of varying severity have been reported by the Government of West Bengal for the last five years.

(f) It is for the State Government to take necessary steps to combat the situation created by flood conditions. The Government of India only supplements the efforts of the State Government by providing Central assistance to tackle the situation effectively.

स्वयं वित्तीय योजना IV के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा राशियों पर ब्याज

699. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कालोनियों मे स्वयं-वित्तीय योजना IV के अन्तर्गत जो मकान आवंटित किए गए थे वे मकान कुछ कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण और उसके ठेकेदारों के बीच झगडे तथा सांठगांठ के कारण समय पर नही सौंपे गए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन आवंटितियों को जमा राशि पर इस विलम्ब के कारण बीते हुए समय के लिये कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार स्वय वित्तीय योजना-IV के आवंटितियो को उनकी जमा धन-राशि पर ब्याज देने का विचार रखती है, यदि हा, तो कब तक : क्या इस सम्बन्ध में किसी अनियमितता का पता लगा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तर दिया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और ठेकेदारों के मध्य विवाद तथा साठ-गांठ का कोई मामला उनके ध्यान मे नही आया है जिसके स्व-वित्त पोषित योजना IV के अन्तर्गत आवंटियों को मकान का कब्जा देने में विलम्ब हुआ हो ।